

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी किये गये

06.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अक्रियान्वित आस्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत साठ दिवस का नोटिस जरिए रजि. डाक प्रेषित किया गया, उक्त मांग नोटिस की पावती बैं को प्राप्त नहीं होने/मांग नोटिस बिना तामील लौट आने के कारण नियमानुसार मांग नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्र में करवाया गया। परन्तु ऋण द्वारा बकाया राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में बैंक के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थी को प्रेषित किये गये रजि. नोटिस अप्रार्थीगण पर तामील नहीं होने के कारण नियमानुसार धारा 13(2) के नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार -

" Demand Notice

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and



प्र.सं. 58/2024 जीसीएमएस नं. 2024/87 अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. बनाम मै. बालाजी एजेंसी आदि

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी किये गये

also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the branches of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand notice shall be served on each borrower.

उक्त नियम के अनुसार यदि रजि. नोटिस की तामील नहीं होती है तो ऋणि के आवास/कार्यस्थल स्थान पर नोटिस चस्पा करने तथा दो प्रचलित समचार पत्रों में नोटिस प्रकाशन द्वारा तामील करवाए जाने के प्रावधान हैं। प्रकरण में नोटिस के ऋणि के आवास अथवा अन्य स्थान पर चस्पा किये जाने संबंधित कोई तथ्य पत्रावली में अंकित नहीं किया है ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्राधिकृत पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वे इस आशय हेतु बैंक की ओर से अधिकृत हैं। हस्तगत प्रकरण में उक्त नियम 3 के अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस विधिवत तामील होना नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी द्वारा विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 06.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़